पत्रांक –3/एम०–17/2020सा0प्र0 6831 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

गुफ़रान अहमद
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक
सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 23.07.2020

विषय– राज्याधीन सेवाओं/संवर्गों में नियुक्ति हेतु संबंधित आयोग से अनुशंसित अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही में दोषसिद्ध होने/प्रक्रियाधीन रहने की स्थिति में नियुक्ति करने हेतु दिशा–निर्देश।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्याधीन सेवाओं/संवर्गों में सीधी भर्त्ती/नियुक्ति हेतु संबंधित आयोग से अनुशंसित अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त स्वच्छ होना उनकी नियुक्ति की अनिवार्य शर्त्त है।

2. बिहार सरकार में स्वच्छ छवि के पदाधिकारी/कर्मचारी नियुक्त हो सकें, इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–1859 दिनांक–08.07.2006 द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन का प्रावधान किया गया है। अभिलेखों की जाँच के क्रम में एतदर्थ निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित सूचनाएँ अनुशंसित अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अंकित की जानी होती है। प्रपत्र के कंडिका–12 में उनके विरुद्ध चल रही/लंबित आपराधिक मामलों से संबंधित सूचनाएँ भी अंकित की जानी होती है।

3. उक्त क्रम में सत्यापन प्रपत्र में किसी अनुशंसित अभ्यर्थी द्वारा उसके विरुद्ध आपराधिक मामलों से संबंधित अंकित की गयी सूचना के आधार पर अथवा उसके द्वारा जानबूझकर सूचना छुपाये जाने की स्थिति में उसके अभ्यर्थित्व के संबंध में संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किस प्रकार निर्णय लिया जाय, इस संदर्भ में एक मार्गदर्शन निर्गत करने का प्रस्ताव विचाराधीन था।

4. विचाराधीन विषय के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–18798/2017 (एस0एल0पी0सं0–20525/2011 से उद्भूत) अवतार सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक–15.11.2017 को एक महत्त्वपूर्ण आदेश पारित किया गया है। उक्त न्यायादेश की कंडिका–38 में विचाराधीन विषय के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन निर्धारित है, जो निम्नवत् है–

> "4. In Avtar Singh v. Union of India and Others, reported in (2016) 8 SCC 471, this Court has considered in detail as to the circumstances under which the stringent action could be taken and to what extent the employer can exercise its discretion. Relevant portion reads as follows:-
>
> 38.1 Information given to the employer by a candidate as to conviction, acquittal or arrest, or pendency of a criminal case, whether before or after entering into service must be true and there should be no suppression or false mention of required information.
>
> 38.2. While passing order of termination of services or cancellation of candidature for giving false information, the employer may take

notice of special circumstances of the case, if any, while giving such information.

38.3. The employer shall take into consideration the Government orders/instructions/rules, applicable to the employee, at the time of taking the decision.

38.4. In case there is suppression or false information of involvement in a criminal case where conviction or acquittal had already been recorded before filling of the application/verification form and such fact later comes to knowledge of employer, any of the following recourse appropriate to the case may be adopted :

38.4.1. In a case trivial in nature in which conviction had been recorded, such as shouting slogans at young age or for a petty offence which if disclosed would not have rendered an incumbent unfit for post in question, the employer may, in its discretion, ignore such suppression of fact or false information by condoning the lapse.

38.4.2 Where conviction has been recorded in case which is not trivial in nature, employer may cancel candidature or terminate services of the employee.

38.4.3 If acquittal had already been recorded in a case involving moral turpitude or offence of heinous/serious nature, on technical ground and it is not a case of clean acquittal, or benefit of reasonable doubt has been given, the employer may consider all relevant facts available as to antecedents, and may take appropriate decision as to the continuance of the employee.

38.5. In a case where the employee has made declaration truthfully of a concluded criminal case, the employer still has the right to consider antecedents, and cannot be compelled to appoint the candidate.

38.6. In case when fact has been truthfully declared in character verification form regarding pendency of a criminal case of trivial nature, employer, in facts and circumstances of the case, in its discretion may appoint the candidate subject to decision of such case.

38.7. In a case of deliberate suppression of fact with respect to multiple pending cases such false information by itself will assume significance and an employer may pass appropriate order cancelling candidature or terminating services as appointment of a person against whom multiple criminal cases were pending may not be proper.

38.8. If criminal case was pending but not known to the candidate at the time of filling the form, still it may have adverse impact and the appointing authority would take decision after considering the seriousness of the crime.

38.9. In case the employee is confirmed in service, holding Departmental enquiry would be necessary before passing order of termination/removal or dismissal on the ground of suppression or submitting false information in verification form.

38.10. For determining suppression or false information attestation/verification form has to be specific, not vague. Only such information which was required to be specifically mentioned has to be disclosed. If information not asked for but is relevant comes to knowledge of the employer the same can be considered in an objective

manner while addressing the question of fitness. However, in such cases action cannot be taken on basis of suppression or submitting false information as to a fact which was not even asked for.

38.11. Before a person is held guilty of suppressio veri or suggestio falsi, knowledge of the fact must be attributable to him."

5. उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्याधीन सेवाओं/संवर्गों में नियुक्ति हेतु संबंधित आयोग से अनुशंसित अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही में दोषसिद्ध होने/प्रक्रियाधीन रहने की स्थिति में नियुक्ति करने हेतु निम्नवत् मार्गदर्शन निर्गत किया जाता है–

(1) संबंधित आयोग/चयन समिति से सीधी भर्त्ती/नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त होने पर अभिलेखों की जाँच के क्रम में अनुशंसित अभ्यर्थियों को पूर्ण एवं सही सूचनाएँ अंकित करने का निदेश देते हुए उनसे चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन हेतु विहित प्रपत्र प्राप्त किया जायेगा।

(2) अनुशंसित अभ्यर्थियों से प्राप्त चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र को सत्यापन हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से पुलिस/अपराध अनुसंधान विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) संबंधित एजेंसी से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र सत्यापित होकर प्राप्त होने के उपरान्त ही सक्षम नियुक्ति प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्ति की कार्रवाई की जा सकेगी।

(4) इस क्रम में प्रपत्र में अभ्यर्थी अथवा सत्यापन एजेंसी द्वारा आपराधिक मामला के संदर्भ में कोई सूचना अंकित किये जाने अथवा सत्यापित/प्रतिवेदित किये जाने की स्थिति में उपर्युक्त कंडिका–4 में अंकित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–18798/2017 (एस0एल0पी0सं0– 20525/2011 से उद्भूत) अवतार सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक–15.11.2017 को दिये गये मार्गदर्शन के आलोक में संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा गुण–दोष के आधार पर case–to-case विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

6. कृपया उपर्युक्त अनुदेशों से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

23/7/2020

(गुफ़रान अहमद)
सरकार के उप सचिव।